



श्रम संगम

वर्ष: 8, अंक: 2

जुलाई-दिसंबर 2022



वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

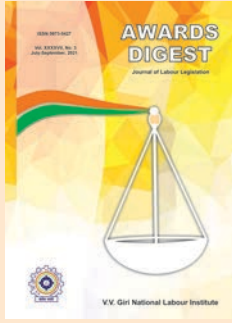
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छामाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ-साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।



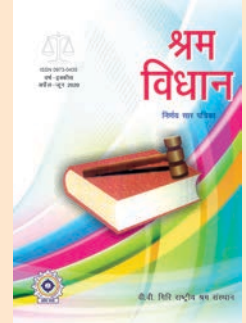
अवार्ड्स डाइजेस्ट: श्रम विधान का जर्नल



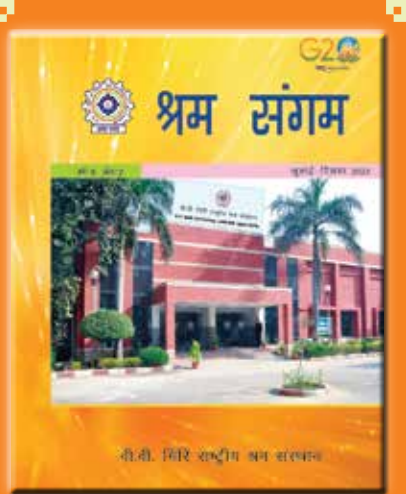
अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रमकानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय-समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के साथ-साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।



चंदे की दर: लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए व



मुख्य संरक्षक
श्री अमित निर्मल
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. संजय उपाध्याय
वरिष्ठ फेलो

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सेक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रण: चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

श्रम संगम

वर्ष: 8, अंक: 2, जुलाई-दिसंबर 2022

अनुक्रमणिका

○ महानिदेशक की कलम से	ii
○ नोबेल पुरस्कार विजेता: वैक्टरमन रामकृष्णन - डॉ. संजय उपाध्याय	1
○ प्यारा देश अपना (कविता) - बीरेन्द्र सिंह रावत	3
○ वैश्विक हिंदी का स्वरूप और विश्व में हिंदी - राकेश कुमार	4
○ एक देश, एक चुनाव की आवश्यकता - राजेश कुमार कर्ण	7
○ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक - बीरेन्द्र सिंह रावत	11
○ वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा - 2022 का आयोजन	14
○ कुर्सियाँ (कविता) - राकेश कुमार	15
○ एक मोमबत्ती हम भी जलाएँ (कविता) - श्याम कुमार	15
○ जब तुम उठी.....प्रेरक अंतरात्मा (कविता) -डॉ. एलीना सामंतराय	16
○ एजेंडे में जल, जीवन और जलवायु परिवर्तन - राजेश कुमार कर्ण	17
○ कार	

महानिदेशक की कलम से...



भारत विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ की संस्कृति, वेश-भूषा, खान-पान, रहन-सहन, बोली-भाषा एवं विचारों आदि में भिन्नता है। हमारे देश की भाषायी विविधता एवं बहुआयामी संस्कृति के बावजूद इसे एक सूत्र में बाँधे रखने में हिंदी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। यहाँ, यह और भी उल्लेखनीय है कि हिंदी की आवाज पहले अहिंदी प्रांतों से उठी। अगर हम हिंदी की

विकास यात्रा पर गौर करें तो यह पाते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का विचार सबसे पहले प्रसिद्ध गुजराती कवि व विद्वान वक्ता नर्मद (मूल नाम – नर्मदाशंकर लालशंकर दवे) ने उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रखा था। उनके महान कार्यों को सम्मान देने और राजभाषा हिंदी के अखिल भारतीय प्रसार को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 14-15 सितंबर 2022 को हिंदी दिवस समारोह एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत, गुजरात में आयोजित किया गया।

राजभाषा हिंदी, जनता और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अतः सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ ही उनका लाभ आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकारी कार्यालयों में अधिक से अधिक काम हिंदी में हो। सरकारी कर्मचारी होने के साथ-साथ भारत के एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से हम सबका यह नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने कार्यलयीन कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा दें। मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि हम सभी के सामूहिक प्रयासों से हिंदी के कार्यलयीन प्रयोग में दिनोंदिन वृद्धि होगी।

संस्थान की राजभाषा पत्रिका 'श्रम संगम' की नियमितता बनाए रखने तथा इसके आगामी अंकों को अधिकाधिक रुचिकर बनाने हेतु आपके बहुमूल्य विचारों और सुझावों का सदैव स्वागत है। पत्रिका अनवरत इसी प्रकार आकर्षक रूप में हमारे बीच आती रहे तथा हिंदी के प्रचार-प्रसार में सदैव सफलता प्राप्त करे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

(अमित निर्मल)

नोबेल पुरस्कार विजेता: वेंकटरमन रामकृष्णन

डॉ. संजय उपाध्याय*



विज्ञान के क्षेत्र में अप्रतिम स्थान रखने वाले और अपने उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से मानवता की सतत सेवा कर रहे भारतीय मूल के ब्रिटिश-अमेरिकी वैज्ञानिक (स्ट्रक्चरल बायोलोजिस्ट) वेंकटरमन रामकृष्णन जी को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 2009 का नोबेल पुरस्कार

अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस ए. स्टेट्ज और इजरायल की वैज्ञानिक अदा ई. योनथ के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। वेंकटरमन जी की महती गाथा संसार के उस हर प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के सामने है जो अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है। उनका जीवन और योगदान उस हर युवक के सामने एक मिसाल है जो अपनी आंखों में भविष्य के सपने सजाए हुए है। यह इस बात का सर्वोत्तम उदाहरण है कि अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी आसानी से हर मुश्किल को पार कर मंजिल तक पहुंच सकता है।

आरंभिक जीवन

वेंकटरमन रामकृष्णन का जन्म वर्ष 1952 में एक दक्षिण भारतीय परिवार में हुआ था। तमिलनाडु के कुड्डलूर जिले के चिदंबरम नामक स्थान पर जन्मे वेंकटरमन रामकृष्णन के पिता सी. वी. रामकृष्णन वैज्ञानिक और माता राजलक्ष्

रोजनबेरी की अद्भुत कल्पनाशीलता एवं उनकी भावनाओं से बेहद लगाव था। एक-दूसरे की भावनाओं को भली भांति समझने और उन्हें अनुभूत करने के बाद अंततः दोनों ने वैवाहिक बंधन में बंधकर जीवनभर साथ रहने का निश्चय किया। अपने इस निश्चय के बाद अंततः दोनों ने विवाह कर लिया। उनका बेटा रमन और बहू मेलिसा रियरडान संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अच्छा नाम कमा रहे हैं।

शोधकार्य

अपने दोस्तों में प्यार से 'वेंकी' कहे जाने वाले वेंकटरमन जी ने अपने कैरियर की शुरुआत राइबोसोम की संरचना एवं कार्य प्रणाली के अध्ययन से शुरू की। वे येल यूनिवर्सिटी में अपने एक परम मित्र पीटर मूर के साथ राइबोसोम के अध्ययन में पूरी तरह जुट गए।

राइबोसोम मूल रूप से प्रत्येक कोशिका में निहित एक बहुत छोटा कण होता है जिसकी लम्बाई कोशिका में कुल 20 नैनो मीटर के बराबर होती है। यह DNA में आनुवंशिक गुणों के संवाहक प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। यह शरीर में रासायनिक परिवर्तनों को नियंत्रित करता है तथा ऐसे रासायनिक तत्वों का निर्माण करता है जो इस नियंत्रण में सहायता करते हैं। राइबोसोम कई अलग तरह के रूपों में तथा कई तरह के अलग कार्यों में निरत भी पाया जाता है।

शरीर के सारे तत्व इन्हीं रासायनिक परिवर्तनों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि हीमोग्लोब

कॉलेज ऑफ कैमिस्ट्री के फेलो हैं। 2007 में उन्हें लुईस जीनटेट प्राइज फॉर मेडिसिन से नवाजा गया था। वर्ष 2009 में गोएथ यूनिवर्सिटी फैंकफुर्ट द्वारा राल्फ सैमेट प्रोफेसरशिप से सम्मानित किया गया। 09 सितंबर 2009 को राइबोसोम्स की खोज के लिए उन्हें अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस ए. स्टेट्ज और इजरायल की वैज्ञानिक अदा ई. योनथ के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2010 में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2012 में मोलेक्यूलर बायोलॉजी में सेवा के लिए नाइट बैचलर (नाइटहुड) की उपाधि से नवाजा गया। उनके अनेकों लेख और शोध नेचर मैगजीन सहित अनेकों पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं।

हाल ही में उन्होंने दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक व्याख्यान के दौरान यह विचार रखे कि

किसी भी राष्ट्र की वास्तविक संपदा उसके नवाचारों और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में उसके योगदान पर निर्भर करती है। विज्ञान और इस पर होने वाले व्यय को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया एक बहुत कम समय में कोविड-19 के विरुद्ध वैक्सीन इसलिए विकसित कर पाई क्योंकि इस दिशा में काफी कुछ वैज्ञानिक ज्ञान काफी पहले ही अस्तित्व में आ चुका था। साथ ही, उन्होंने यह विचार रखे कि विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक होता है कि विज्ञान को राजनीति से दूर रखा जाए और युवा वैज्ञानिकों के लिए धन की कमी आड़े न आए जिससे कि वे निश्चित होकर नौकरशाही के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ अपना ध्यान शोध पर केन्द्रित करते हुए अपना योगदान कर सकें।

वैश्विक हिंदी का स्वरूप और विश्व में हिंदी

राकेश कुमार*



12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में होने जा रहा है और इसकी तैयारियां जोर-शोर से चल भी रही हैं। 'विश्व हिंदी सम्मेलन' की संकल्पना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा की गई थी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के ही तत्वावधान में तीन-दिवसीय प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन चूंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया, इसीलिए आगे चलकर प्रतिवर्ष 'विश्व हिंदी दिवस' मनाने के लिए 10 जनवरी की तिथि सुनिश्चित कर दी गई।

पहली बार, विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। सम्मेलन के दौरान जो प्रश्न उठाए गए थे, वे आज 46 साल बाद भी देश के सामने जस के तस खड़े हैं। अब तक कुल 11 विश्व हिंदी सम्मेलन, भारत समेत, दुनिया के कई देशों में सम्पन्न किए जा चुके हैं लेकिन इन सम्मेलनों का वास्तविक नतीजा क्या रहा है, यह सर्वविदित है।

विश्व हिंदी सम्मेलनों का उद्देश्य, पहले सम्मेलन में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि तत्कालीन वैश्विक परिस्थिति में हिंदी को किस प्रकार सेवा का साधन बनाना है। हिंदी, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश पाकर विश्वभाषा के रूप में समस्त मानवजाति की सेवा की ओर अग्रसर हो। साथ ही हिंदी किस प्रकार भारतीय संस्कृति का मूलमंत्र 'वसुधैव कुटुंबकम' विश

में सबसे बड़ा है। यदि हिंदी, संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन जाए तो वह दुनिया की सभी भाषाओं को अपने शब्द-भंडार से भर देगी। यदि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिलेगी तो भारत से अंग्रेजी की गुलामी भी घटेगी। उसका फायदा यह होगा कि दुनिया के चार-पांच अंग्रेजी भाषी देशों के अलावा सभी देशों के साथ व्यापार और कूटनीति में हमारा सीधा संवाद कायम हो सकेगा।

हिंदी भारत की मुख्यभाषा होने के साथ-साथ, इस देश के सरकारी तंत्र की राजभाषा भी है। सदियों से इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में होता आ रहा है। मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में भी हिंदी और हिंदुस्तानी बोलचाल की भाषा रही है। धीरे-धीरे इसने संस्कृत, उर्दू और अन्य भाषाओं की मदद से एक बड़ा शब्द भंडार जुटा लिया है जिससे न केवल साहित्यिक प्रयोजनों के लिए बल्कि कामकाजी प्रयोजनों और उच्च शिक्षा तक में इसका प्रयोग किया जा रहा है। यह और बात है कि इसका प्रयोग जितना आम बोलचाल और संपर्क भाषा के रूप में है, उतना शासन-प्रशासन की भाषा के रूप में नहीं। पूरी दुनिया में हिंदी को बचाए रखने व उसे संवर्धित करने का काम विश्व भर में फैले हिंदी भाषी, प्रवासी, और भारतवंशी कर रहे हैं।

हमारे यहां संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था। तब से भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देश में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक स्तरों पर प्रयत्न किए गए हैं। संविधान में राजभाषा नीति के प्रावधानों के अलावा राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 एवं समय-समय पर दिए गए राष्ट्रपति के आदेशों के कार्यान्वयन एवं संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणों एवं त

रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की आधिकारिकता की। संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषा की 'श्रेष्ठता' स्वीकार कराने के लिए कुछ निर्धारित मानक थे। हिंदी से जुड़े आंकड़ों को लेकर हम वहां खरे नहीं उतरे।

दरअसल, हुआ क्या था कि चीन में भाषा के प्रति राजनीतिक सदिच्छा रही और लाल झंडे तले लालफीताशाही ने देश के सारे नागरिकों से भाषा के कॉलम में एक ही नाम भरवा लिया—'मंदारिन'। हमारे लोकतंत्र में कोई अंकुश तो था नहीं, जनगणना में राज्यवार हमारे नागरिकों ने अपनी अलग-अलग भाषाएं लिख दीं। हालांकि, चीन में भी हमारे देश के समान ही तीस-चालीस भाषाएं अस्तित्व और चलन में थीं। 70 के दशक के प्रारंभ में उनकी आबादी लगभग 70 करोड़ थी। जनगणना के भाषागत सर्वेक्षण के आधार पर, यूएनओ ने स्वीकार कर लिया कि चीनी बोलने वाले 70 करोड़ हैं। इस प्रकार उन्होंने 'मंदारिन' को मान्यता दे दी। संख्या-बल में हम दूसरी महाशक्तियों से भी पिछड़ते गए।

अनेक विद्वान मानते हैं कि हिंदी की महानता और महत्ता तभी मानी जाएगी, जब वह संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता पा जाएगी। विडम्बना देखिए कि वर्ष 1975 से लेकर अब तक ग्यारह विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं लेकिन हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके लिए तमाम औपचारिकताओं का जंजाल पूरा करना पड़ता है।

10वें सम्मेलन की अनुशंसा थी— 'संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को समयबद्ध तरीके से आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संकल्प लिया जाना चाहिए। इस संबंध में अन्य देशों का

एक देश, एक चुनाव की आवश्यकता

राजेश कुमार कर्ण*



लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने का विचार फिर से चर्चा के केंद्र में है। गवर्नेंस का स्तर सुधारने और देश को बार-बार चुनावी चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी जरूरत को रेखांकित किया है। कुछ दिन पहले लोकसभा के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने इस प्रस्ताव पर विस्तार से बताया कि एक साथ चुनाव कराने से न केवल सरकारी खजाने को भारी बचत होगी, बल्कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का व्यय भी घटेगा। इससे बार-बार होने वाले चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के चलते रुकने वाली विकास परियोजनाएं भी प्रभावित नहीं होंगी। हालांकि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी दलों और राज्य सरकारों को एक साक्षा मंच पर आकर कोई युक्ति निकालनी होगी। साथ ही संविधान एवं चुनाव संबंधी कानूनों में भी कुछ संशोधन करने होंगे। सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे की मीमांसा करने का अनुरोध किया है। विधि आयोग 1999 में पहले ही इसके पक्ष में सहमति व्यक्त कर चुका है। विधि आयोग ने 1999 में अपनी 170 पन्नों की रपट में इस मुद्दे की गहनता से पड़ताल की और पुरजोर तरीके से एक साथ चुनाव कराए जाने की पैरवी की। हालांकि उसने यह भी स्वीकार किया कि विभिन्न विधानसभाओं के कार्यकाल चक्र को देखते हुए इसे एकाएक अमल में नहीं लाया जा सकता। उसने उन सभी विधानसभा चुनावों को एक साथ जोड़ने का सुझाव दिया जो अगले 12 महीनों में प्रस्तावित हों। आयोग ने कहा कि यदि

जरूरी है। इतना बड़ा परिवर्तन आसानी से नहीं होने वाला है, कुछ वक्त लगेगा, इसलिए कोई बेसब्री भी नहीं दिखाई जा रही है। 'मैं अकेला नहीं, बल्कि सब मिलकर करेंगे', कहकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे आम राय बनाने के मूड में हैं। इसे संभव बनाने के लिए इस विषय पर व्यापक चर्चा जरूरी है कि एक साथ चुनाव के क्या फायदे हो सकते हैं।

इसके पक्ष में मजबूत तर्क हैं। इससे अथाह धन की बचत होगी जिसका इस्तेमाल विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के आयोजन में 1195 करोड़ रुपए खर्च हुए थे तथा 2014 के चुनाव में 3900 करोड़ रुपए खर्च हुए थे जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 55000 करोड़ रुपए हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में इससे कई गुणा अधिक खर्च होने की आशंका है। एक साथ चुनाव से चुनावों पर लगातार बढ़ता खर्च घटेगा, चुनाव के लिए सरकारी कर्मचारियों को बार-बार चुनाव ड्यूटी पर नहीं भेजना होगा, बार-बार मतदाता सूची बनाने एवं इसमें संशोधन करने से मुक्ति मिलेगी। भारत जैसे विशाल क्षेत्रफल एवं भारी जनसंख्या वाले देश, जहां लगभग 92 करोड़ मतदाता हैं, यहाँ चुनाव कराना एक बहुत ही बड़ा एवं जटिल काम है। बेशक बार-बार चुनाव होने से भारी मात्रा में सार्वजनिक धन बर्बाद होता है। निर्वाचन आयोग भी बार-बार चुनाव कराने के लिए बहुत रकम खर्च करता है जो असल में करदाताओं का ही पैसा है। हालांकि शुरुआत में अतिरिक्त वोटिंग मशीन और कार्यबल की जरूरत काफी बढ़ सकती है लेकिन बेशक लंबी अवधि में खर्च अंततः कम हो सकता है। एक साथ चुनाव की व्यवस्था बेहतर लोकतंत्र और दीर्घकालिक लाभ के लिए हमारा निवेश होगा।

<

चुनाव कराने को कहा। विधानसभा के लिए चुनाव सात महीने बाद हुए, पर इस दौरान राजनीतिक अस्थिरता रही, जिससे शासन-संचालन प्रभावित हुआ। देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोकसभा में जनादेश विपरीत आने पर राज्य में सत्तारूढ़ दल स्वयं को लेकर अनिश्चित हुआ है। इससे शासन में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों तो इन सारी समस्याओं या दिक्कतों से छुटकारा मिल सकता है।

भले ही एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में ये तमाम तर्क वजनदार हैं लेकिन इसके विरोध की दलीलें भी कम दमदार नहीं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से हमारे संविधान के संघीय चरित्र पर चोट पहुंचेगी क्योंकि वोटर स्थानीय या राज्य के मुद्दों को उतना तवज्जो नहीं दे पाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। यह स्थानीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर लोगों के विचार एवं निर्णय को मिला देता है जबकि दोनों बिल्कुल अलग हैं। यह दलील भी दी जाती है कि जब लोग एक ही बूथ पर जाकर विधानसभा एवं लोकसभा के लिए मतदान करेंगे तो इसकी बहुत संभावना है कि वे एक राष्ट्रीय पार्टी के पक्ष में मतदान करें। इससे छोटे और विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा, उनकी भूमिका घट जाएगी और विविधता और गठबंधन की राजनीति कमजोर होगी जबकि इससे लोकतंत्र को मुखरता मिलती है। आईडीएफसी एवं सीएसडीएस और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स के दो प्रोफेसरों द्वारा अतीत में किए गए दोनों अध्ययनों का निष्कर्ष भी यही है कि यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो लोगों द्वारा एक ही पार्टी

है या उसका बजट पास नहीं होता तो क्या होगा? तब क्या चुनाव नहीं करवाए जाएंगे? यदि लोकसभा की अवधि पूरी होने से पहले उसके भंग होने की परिस्थिति पैदा हो जाती है तो नीति आयोग की सिफारिश है कि जब तक अगले सदन का गठन नहीं हो जाता, यह प्रावधान किया जा सकता है कि राष्ट्रपति एक मंत्रिपरिषद बनाकर देश का शासन चलाएं। बहुत से संविधान के जानकारों के अनुसार बिना प्रत्यक्ष जनादेश के बने हुए राष्ट्राध्यक्ष द्वारा शासन का मतलब लोकतंत्र का कत्ल होगा। भारतीय संविधान में भी केन्द्र में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान नहीं है, यहां सरकार केवल प्रधानमंत्री ही चला सकते हैं। ब्रिटेन की प्रधान मंत्री ने 'ब्रेक्जिट' को लेकर दोबारा जनता के सामने जाने का फैसला किया था यह उनका अधिकार है। भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे अधिकार से वंचित क्यों किया जाए? अगर वह लोकसभा भंग कर दोबारा जनादेश प्राप्त करना चाहें, तो उन्हें रोका क्यों जाए? राज्य में भी यदि कोई मुख्यमंत्री विधानसभा भंग कर दोबारा जनादेश प्राप्त करना चाहें तो उनके समक्ष रुकावट क्यों खड़ी की जाए?

कभी-कभी चुनाव के बाद किसी दल अथवा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर भी स्थायी सरकार का गठन संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में राज्य में तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है किंतु केन्द्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है। किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उस व्यक्ति को बगैर लोकसभा का सामना किए छह महीने तक प्रधानमंत्री पद पर बैठने का अधिकार भी होता है। लेकिन एक महीना या एक दिन के लिए भी राष्ट्रपति देश के शासन से जुड़ा कोई काम प्रधानमंत्री की सलाह के बिना नहीं कर सकता। इसलिए यह सवाल उठाया गया है कि लोकसभा के लिए निश्चित पाँच साल के कार्यकाल की व्यवस्था कर

पत्र 'केसरी' था और दूसरा अंग्रेजी का साप्ताहिक समाचार पत्र 'महारात्ता' था। थोड़े समय में ही ये दोनों समाचार पत्रों बहुत प्रसिद्ध हो गए। अपने इन समाचार पत्रों में तिलक भारत की दुर्दशा पर अधिक लिखा करते थे, वे लोगों के कष्टों का और वास्तविक घटनाओं की तस्वीर को इसमें छापते थे। बाल गंगाधर तिलक सबसे कहा करते थे कि अपने हक लिए सामने आकर लड़ो।

राजनीतिक यात्रा

लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। लोकमान्य तिलक ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे, तथा भारतीय अन्तःकरण में अपने समय के सबसे प्रख्यात आमूल परिवर्तनवादियों में से एक थे। उन्होंने माँग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच' (स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा) बहुत प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोकमान्य तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। हालांकि, कांग्रेस के उदारवादी रवैये, खासकर जो स्वराज्य हेतु लड़ाई के प्रति था, के वह खिलाफ थे। लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में 'देश का दुर्भाग्य' नामक शीर्षक से लेख लिखा जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। 1897 में तिलक पर अपने भाषण के द्वारा अशांति फैलाने और राज विरोधी

मांडले जेल से छूटने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने 1916 कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। वह कांग्रेस के दोनों दलों को फिर से जोड़ने की कोशिश करते रहे। उन्होंने इसके लिए महात्मा गाँधी को भी समझाने की कोशिश की कि वे पूरी तरह से अहिंसा को सपोर्ट न करें, बल्कि स्वराज के बारे में भी सोचें। अंततः उनकी ये सारी कोशिशें बेकार गईं। इसके बाद उन्होंने एनी बेसेंट की तर्ज पर अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफी प्रसिद्धि मिली और उनके अनुयायियों ने होमरूल आंदोलन 1916 के दौरान उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। लोकमान्य का अर्थ होता है 'लोगों द्वारा प्रतिष्ठित'। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। यह कोई सत्याग्रह आंदोलन जैसा नहीं था। इसमें चार या पांच लोगों की टुकड़ियां बनाई जाती थी जो पूरे भारत में बड़े-बड़े राजनेताओं और वकीलों से मिलकर होम रूल लीग का मतलब समझाया करते थे। एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत आई हुई थीं। उन्होंने वहां पर होमरूल लीग जैसा प्रयोग देखा था, उसी तरह का प्रयोग उन्होंने भारत में करने का सोचा। तिलक इसके बाद देश भर में भ्रमण करके सबको स्वराज के आन्दोलन से जोड़ने की कोशिश करते रहे। अप्रैल 1916 में लीग में 1400 सदस्य थे और 1917 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 32,000 हो गयी थी। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा 1916 में भी तिलक पर उनके स्व-शासन व्याख्यानों को लेकर तीसरी बार राजद्रोह का आरोप लगाया गया तो जिन्ना (1909 में जब तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया तो तब भी उनके बचाव में बॉम्बे के वकील मुहम्मद अली जिन्ना पेश हुए थे) फिर से उनके वकील थे और इस बार उन्हें



dfll;k

राकेश कुमार*

कुर्सियों पर बैठे लोग,
 कुर्सियों के नहीं होते,
 बिकती नहीं हैं कुर्सियाँ,
 बिक जाते हैं उन पर बैठे लोग।
 गद्देदार, मखमली कुर्सियों में भी,
 लगी होती हैं कीलें,
 आरामदायक कुर्सियों में भी,
 होती है तेज चुभन।
 कुर्सियाँ चुभती हैं बैठने वालों को,
 और कभी-कभी देखने वालों को भी।
 अक्सर चलती हैं कुर्सियाँ,
 उछलती और टूटती भी हैं कुर्सियाँ,
 कभी लगाई जाती और बिछाई जाती हैं कुर्सियाँ,
 फिर धीरे से –
 खींची भी जाती हैं कुर्सियाँ।
 कभी उपेक्षित,
 तो अक्सर अपेक्षित होती हैं कुर्सियाँ।
 कुर्सियों का नहीं होता ईमान,
 मगर—
 कुर्सियों पर बैठे लोग रखते हैं ईमान।
 सिर्फ एक बार बनती हैं,
 पर कई बार बिकती हैं कुर्सियाँ।
 कभी चार,
 तो कभी तीन टांगों पर,
 टंगी होती हैं कुर्सियाँ।
 टांगें खींचने को आतुर,
 लोगों से घिरी होती हैं कुर्सियाँ।
 कुर्सी एक जिम्मेदारी है,
 परंतु कुर्सी पर बैठा आदमी,
 नहीं समझता जिम्मेदारी।
 कहीं कुर्सी पर लदे,
 तो कहीं पसरे हुए हैं लोग।
 ये कुर्सियाँ भी संभाले हुए हैं,
 कैसे-कैसे लोगों का बोझ,
 जो हो नहीं पाते कहीं के,
 वे हो जाते हैं कुर्सी के।
 ना जाने कैसे-कैसे का बोझ,
 कुर्सियाँ अपने पर उठाए हुए हैं



जब तुम उठी.....प्रेरक अंतरात्मा

डॉ. एलीना सामंतराय*

नारी, तुम एक प्रेरक आत्मा।
जीत के लिए जनित, हासिल करने के लिए जीवित,
प्रयत्नों के लिए जनित।
मायने नहीं किसी तारीख के,
महत्त्व नहीं तुम्हारी ओर घूरती,
उन धिनौनी नफरत भरी, पगलाई सी बुरी निगाहों के,
जैसे तुम थी सदा से-----इस सुंदर मानवीय सदन में,
एक अनचाही, कमतर, नश्वर आत्मा,
स्थानहीन, महत्वहीन।
तुम्हारी वे चमकती आँखें,
जो उत्सुक हैं-----इस दुनिया को देखने को,
लौकिक जिज्ञासा के साथ-----..
अपने स्वर्गिक निवास से आगे बढ़ती हुई,
ओह प्रेरक आत्मा।
तुम श्वेत मोती के समान शुद्ध, गंगा जल के समान
पवित्र,
कसमसाते आलिंगन में जकड़ी, प्रेमपाश में बंधी,
करुणा, दया और क्षमा से परिपूर्ण,
ओह! एक प्रेरक आत्मा।
आह! तुम प्रेरक अंतरात्मा।
कैसे समझूँ.....तुम अनचाही, अयाचित, मूल्यहीन हो ?
अनियंत्रित रास्तों से निकलती हुई,
उदार, बंधन—मुक्त शक्ति तुम,
ऊँची उड़ान भरती हुई.....
नेतृत्व से परिपूर्ण, क्योंकि तुम हो प्रेरक आत्मा।
सबकी परवाह करती हुई, जो रहे सदा उपेक्षित,
सबको स्नेह देती हुई, जो रहे स्नेहविहीन जीवन भर,
सभी का हाल पूछती हुई, जो रहे सदा याचक,</

जारी होते रहते हैं कि पीएम2.5 का क्या स्तर होना चाहिए, फिर भी हमारे शहरों में इसका स्तर ज्यादा पाया जाता है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें शहरों में ही नहीं, बल्कि उनके आसपास के इलाकों, यहां तक कि गांव के स्तर पर भी कदम उठाने की जरूरत है। प्रदूषण कम करने की योजनाएं अब केवल शहर केंद्रित न रहें, उनका दायरा बढ़ाना पड़ेगा। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था कि राज्य स्तर पर एक्शन प्लान बनाए जाएं, मगर अनेक राज्यों में यह अब तक नहीं बना या बनाया जा रहा है। हर राज्य और शहर को अपनी-अपनी स्थिति को देखते हुए तय करना चाहिए कि प्रदूषण को कब तक कितना कम कर देना है। श्री विवेक चट्टोपाध्याय ने ठीक ही लिखा है कि अभी प्रदूषण घटाने का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वह पीएम पार्टिकल्स पर केंद्रित है। इसमें ओजोन, नाइट्रोजन व अन्य प्रदूषक तत्वों को भी लाया जाना चाहिए। योजना बना देना या दिशा-निर्देश जारी कर देना ही काफी नहीं है, जमीनी स्तर पर कार्यों की निगरानी करनी पड़ेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण हर साल होता है, इसके साथ ही प्रदूषण निवारण योजनाओं और किसने प्रदूषण घटाने के लिए कितना काम किया, इसका भी सर्वेक्षण होना चाहिए। लोगों के सामने

आना चाहिए कि किस शहर में प्रदूषण घटाने के लिए क्या किया गया और उसमें कितनी कामयाबी मिली। शहरों को एक-दूसरे से प्रदूषण घटाना सीखना होगा। कई शहरों में कूड़े के पहाड़ हट नहीं रहे हैं। सफाई का काम मौसमी नहीं है, यह काम साल भर समान रूप से चलना चाहिए, तभी नतीजे दिखेंगे। निरंतर काम और लगातार निगरानी से ही हवा सांस लेने लायक हो सकती है। भारत में चार हजार से ज्यादा शहर हैं, पर ज्यादातर शहरों में प्रदूषण की उचित निगरानी नहीं हो रही है। यदि प्रदूषण को पैदा होने

